

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 13 अप्रैल, 2011
विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में सहकारिता विभाग के सहकारिता न्यायाधिकरण की
आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-18385/लेखा-बजट/2011-12 दिनांक 31 मार्च, 2011, वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या:-209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में सहकारिता विभाग के सहकारिता न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में कुल धनराशि ₹ 38,04,000/- (रुपये अड़तीस लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह में 5 तारीख तक बी0एम0-5 प्रपत्रपर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।
6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2- उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता आयोजनेत्तर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05-सहकारिता न्यायधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा:-

मानक मद व मद का नाम	धनराशि (हजार ₹0 में)
01- वेतन	2000
02- मजदूरी	5
03- महंगाई भत्ता	1200
06- अन्य भत्ते	220
08- कार्यालय व्यय	3
09- विद्युत देय	20
10- जलकर/जलप्रभार	10
13- टेलीफोन पर व्यय	12
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	50
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	250
22- आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	3
27- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	6
45- अवकाश यात्रा व्यय	2
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	3
योग	3804

(₹0 अड़तीस लाख चार हजार मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:-209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या:-611 (1)/XIV-1/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-4/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. मा0 अध्यक्ष, सहकारिता न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रभारी मिडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फ़ावली हेतु।

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।